



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 2019/कार्तिक 8, 1941
No. 371] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2019/KARTIKA 8, 1941

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2019

दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रिसेबल प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2019

(2019 का 7)

फा.सं. 21-6/2019-बीएंडसीएस.—केंद्र सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39, जो –

(ए) भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) और धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(बी) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड 3 में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या एसओ 44 (ई) और 45 (ई) के तहत प्रकाशित की गई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रिसेबल प्रणाली) विनियम, 2017 (2017 का 1) में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

- (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रिसेबल प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का 7) कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रिसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (इसके पश्चात् मूल विनियमों के रूप में कहा जाएगा) के नियम 15 – (ए) के उप विनियम (1), के प्रथम परंतुक को निम्नलिखित परंतुक से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“बशर्त यह कि प्राधिकरण, इस अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए अंकेक्षकों का पैनल बना सकता है और टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह, मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, या पैनल में रखे गए अंकेक्षकों में से किसी से, इस उप-विनियम के अंतर्गत अंकेक्षण कराए;

(बी) उप-विनियम (1) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे:

“(1ए) यदि वितरक अपने सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम और अन्य संबंधित प्रणालियों की उप-विनियम (1) की अपेक्षाानुसार, वर्ष में एक बार अंकेक्षण कराने में विफल रहता है तो उन्हें इसके लाइसेंस या अनुमति या पंजीकरण के नियम एवं शर्तों या अधिनियम या नियमावली या आदेश या इनके तहत निर्गत निदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण के आदेश, निदेशानुसार, वित्तीय निरुत्साहन के रूप में देय तिथि के बाद, तीस दिनों तक एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और देय तिथि के बाद तीस दिनों के बाद भी चूक जारी रहने पर, दो हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा:

बशर्ते इस उप-विनियम के तहत प्राधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले वित्तीय निरुत्साहन की राशि किसी भी मामले में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगी :

बशर्ते यह भी कि प्राधिकरण द्वारा वित्तीय निरुत्साहन के रूप में किसी भी राशि का भुगतान करने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा देखे गए विनियमों के उल्लंघन के खिलाफ वितरक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर न दिया गया हो।” ;

(सी) उप विनियम (2) के प्रथम परंतुक को निम्नलिखित परंतुक से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“बशर्ते यह कि प्राधिकरण, इस अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए अंकेक्षकों का पैनल बना सकता है और प्रत्येक प्रसारक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह, मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, या पैनल में रखे गए अंकेक्षकों में से किसी से, इस उप-विनियम के अंतर्गत अंकेक्षण कराए;

3. मूल विनियमों की अनुसूची III के लिए निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, नामतः:-

“अनुसूची III

(विनियम 10 का उप-विनियम (6) और विनियम 15 देखें)

अंकेक्षण का स्कोप और शडयूलिंग

(क) **स्कोप:** वितरक द्वारा कराई जाने वाली वार्षिक अंकेक्षण में विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, इस शडयूल के अनुपालन की पुष्टि करने की अंकेक्षण और सब्सक्रिप्शन अंकेक्षण शामिल होगी।

(ख) **शडयूलिंग:** विनियम 15 (1) के तहत वितरक द्वारा अंकेक्षण इस तरह से शडयूल की जाएगी कि दो कैलेंडर वर्षों के अंकेक्षण के बीच कम से कम छह माह का अंतराल हो। इसके अलावा, दो कैलेंडर वर्षों के अंकेक्षण के बीच 18 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए।

एड्रेसेबल सिस्टम की अपेक्षाएं

(ग) कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएसएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस):

1. टेलीविजन चैनलों के वितरक को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा कार्यान्वित सीएसएस का मौजूदा संस्करण का हैकिंग का कोई इतिहास नहीं है।
स्पष्टीकरण: इस संबंध में सीएसएस वैडर से वितरक के पास उपलब्ध लिखित घोषणा का अर्थ इस अपेक्षा का अनुपालन माना जायेगा।
2. एसएमएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन कमांड सहित, मगर इन्हीं तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए लॉग्स को जनरेट, रिकार्ड और मैटेन करने के लिए एसएमएस स्वतंत्र रूप से समर्थ होगा।
3. सीएसएस और एसएमएस में दर्ज डाटा और लॉग्स में बदलाव करना संभव नहीं होगा।
4. टेलीविजन चैनलों का वितरक प्रमाणित करेगा कि उसके द्वारा कार्यान्वित सीएसएस में सीधे सीएसएस टर्मिनल से सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) को एक्टीवेट और डिएक्टीवेट करने की सुविधा नहीं है। एसटीबी के सभी एक्टीवेशन और डिएक्टीवेशन एसएमएस की कमांड से किया जाएंगे।
5. एसएमएस और सीएसएस को इस तरह से एकीकृत किया जाएगा कि दोनों सिस्टम में एसटीबी का एक्टीवेशन और डिएक्टीवेशन एक साथ हों।
स्पष्टीकरण: आवश्यक और पर्याप्त विधियां उपलब्ध होंगी ताकि एसटीबी का प्रत्येक एक्टीवेशन और डिएक्टीवेशन एसएमएस और सीएसएस टर्मिनलों में जनरेट होने वाली रिपोर्टों में प्रदर्शित हों।
6. टेलीविजन चैनलों का वितरक प्रमाणित करेगा कि सीएसएस में एसटीबी ओवर-द-एयर (ओटीए) अपग्रेड करने की क्षमता है ताकि जुड़े एसटीबी को हैकिंग की स्थिति में अपग्रेड किया जा सकें।
7. किसी उपकरण या सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से फिंगरप्रिंटिंग अमान्य नहीं होने चाहिए।
8. सीएसएस और एसएमएस 24 घंटे के भीतर वितरकों के उपभोक्ताओं की संख्या के कम से कम पांच प्रतिशत (5%) एसटीबी या सेवाओं को एक्टीवेट या डिएक्टीवेट करने में समर्थ होने चाहिए।
9. कंटेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसटीबी और व्यूइंग कार्ड (वीसी) को एसएमएस से युग्मित किया जाएगा।

10. सीएस और एसएमएस चैनल बाई चैनल और एसटीबी बाई एसटीबी के आधार पर रिपोर्ट जनरेट करने के उद्देश्य के लिए उपभोक्ताओं को एकल रूप से एड्रेस करने में समर्थ होने चाहिए।
11. एसएमएस कंप्यूटीकृत होना चाहिए और उपभोक्ताओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना और डाटा को रिकार्ड करने में समर्थ होना चाहिए जैसे:
- क. विशिष्ट ग्राहक पहचान (आईडी)
 - ख. सब्सक्रिप्शन कान्ट्रैक्ट नंबर
 - ग. उपभोक्ता का नाम
 - घ. बिलिंग का पता
 - ङ. इंस्टॉलेशन का पता
 - च. लैंडलाइन टेलीफोन नंबर
 - छ. मोबाइल टेलीफोन नंबर
 - ज. ईमेल एड्रेस
 - झ. सब्सक्राइब किए गए चैनल (चैनलों), बुके (बुकों) और सेवाएं
 - ञ. विशिष्ट एसटीबी नंबर
 - ट. विशिष्ट वीसी नंबर
12. एसएमएस निम्नलिखित में समर्थ होना चाहिए:
- क. एसटीबी के एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन के संबंध में ऐतिहासिक डाटा को देखना और मुद्रित करना।
 - ख. संस्थापित प्रत्येक एसटीबी और वीसी का पता लगाना।
 - ग. प्रत्येक उपभोक्ता के लिए शुल्क में बदलाव और उपभोक्ता द्वारा किए गए अनुरोध के तदनुरूपी स्रोत के ऐतिहासिक डाटा को जनरेट करना।
13. एसएमएस को निम्नलिखित के संबंध में वांछित समय पर रिपोर्ट जनरेट करने में समर्थ होना चाहिए:
- i. पंजीकृत उपभोक्ताओं की कुल संख्या
 - ii. सक्रिय उपभोक्ताओं की कुल संख्या
 - iii. अस्थायी रूप से निलंबित उपभोक्ताओं की कुल संख्या
 - iv. डिएक्टीवेट किए गए उपभोक्ताओं की कुल संख्या
 - v. सिस्टम में काली सूची में डाले गए एसटीबी की सूची।
 - vi. विनिर्धारित फॉर्मेट में चैनल (चैनलों), बुके (बुकों) वार मासिक उपभोक्ता रिपोर्ट।
 - vii. प्रत्येक बुके के भाग के रूप में शामिल चैनलों के नाम।
 - viii. निर्धारित समय पर चैनल या बुके विशेष के सब्सक्राइब करने वाले सक्रिय उपभोक्ताओं की कुल संख्या।
 - ix. उपभोक्ता द्वारा सब्सक्राइब किए गए अला-कार्टे चैनल (चैनलों) और बुके (बुकों) के नाम।
 - x. चैनल या बुके विशेष के शुल्क के लिए एजिंग रिपोर्ट।
14. सीएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एसएमएस द्वारा जारी एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन कमांड सहित, मगर इन्हीं तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए लॉग्स को जनरेट, रिकार्ड और मॉटेन करने के लिए सीएस स्वतंत्र रूप से समर्थ होगा।
15. सीएस ऐसे वीसी नंबरों और एसटीबी नंबरों को टैग करने और काली सूची में डालने में समर्थ होगा जो विगत में पाइरेसी में शामिल रहे हैं ताकि ऐसे वीसी या एसटीबी दुबारा कार्यान्वित न किए जा सकें।
16. यह सीएस के लॉग्स से निम्नलिखित रिपोर्टें जनरेट करने में समर्थ होगा:
- क. एसटीबी-वीसी पेयरिंग/डिपेयरिंग
 - ख. एसटीबी एक्टीवेशन/डिएक्टीवेशन
 - ग. एसटीबी के लिए नियत चैनल
 - घ. निर्धारित अवधि के लिए चैनल विशेष के एक्टीवेशन या डिएक्टीवेशन की रिपोर्ट।
17. एसएमएस मदवार विवरण जैसे सब्सक्राइब किए गए चैनलों की संख्या, सब्सक्राइब किए गए चैनलों की रेंटल राशि, ग्राहक परिसर उपस्कर हेतु रेंटल राशि, तननुरूपी पे चैनल (चैनलों) और पे चैनलों के बुके (बुकों) की सूची और खुदरा मूल्य और कर सहित पे चैनल (चैनलों) और पे चैनलों के बुके (बुकों) के लिए प्रभार के साथ प्रत्येक उपभोक्ता के लिए बिल जनरेट करने में समर्थ होगा।
18. वितरक सुनिश्चित करेगा कि सीएस और एसएमएस वैंडर (वैंडरों) के पास वर्षभर **24x7** आधार पर सिस्टम को मॉटेन करने की क्षमता है।
19. टेलीविजन चैनलों का वितरक चैनलों के वितरण के लिए कार्यान्वित सीएस और एसएमएस के विवरण की घोषणा करेगा। किसी अतिरिक्त सीएस/एसएमएस को कार्यान्वित करने के मामले में, वितरक द्वारा इसकी सूचना प्रसारकों को दी जाएगी।
20. किसी उपभोक्ता को एसएमएस से डिएक्टीवेट करने के मामले में सभी कार्यक्रम/सेवाएं उस उपभोक्ता के लिए बंद कर दी जाएंगी।
21. टेलीविजन चैनलों के वितरक को सीएस और एसएमएस के असंपादित डाटा को कम से कम दो वर्ष के लिए संभाल कर रखना होगा।

(घ) फिंगरप्रिंटिंग:

1. टेलीविजन चैनलों का वितरक सुनिश्चित करेगा कि इसके पास नियमित अंतराल पर फिंगर प्रिंटिंग चलाने के लिए सिस्टम, प्रोसेस और कंट्रोल हैं।
2. एसटीबी फिंगर प्रिंटिंग के विजिबल और कवर्ट टाइप को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए।
बशर्त इन संशोधन विनियमों के लागू होने के बाद लगाए गए एसटीबी केवल कवर्ट फिंगर प्रिंटिंग को सपोर्ट करेंगे।
3. किसी भी डिवाइस या सॉफ्टवेयर द्वारा फिंगरप्रिंटिंग को अमान्य नहीं किया जाना चाहिए।
4. फिंगर प्रिंटिंग एसटीबी के रिमोट पर किसी बटन (की) को दबाने पर विलुप्त होने वाली नहीं होनी चाहिए।
5. फिंगर प्रिंटिंग वीडियो की सबसे ऊपरी सतह पर होनी चाहिए।
6. फिंगर प्रिंटिंग इस तरह होनी चाहिए कि यह विशिष्ट एसटीबी नंबर या विशिष्ट वीसी नंबर को पहचान सकें।
7. फिंगर प्रिंटिंग एसटीबी की सभी स्क्रीनों जैसे मेन्यू, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी), सेटिंग्स, नो कंटेंट स्क्रीन और गेम्स आदि पर प्रदर्शित होनी चाहिए।
8. फिंगरप्रिंट की लोकेशन, फॉट कलर और बैकग्राउंड कलर हेड एंड से परिवर्तनीय होना चाहिए और ब्यूविंग डिवाइस पर रैंडम होना चाहिए।
9. फिंगर प्रिंटिंग विशिष्ट एसटीबी और/या वीसी की पहचान करने के लिए करेक्टरों की संख्या को बताने में समर्थ होनी चाहिए।
10. फिंगर प्रिंटिंग ग्लोबल के साथ-साथ एकल एसटीबी आधार पर संभव होनी चाहिए।
11. ओवर्ट फिंगर प्रिंटिंग टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा समय, लोकेशन, अवधि, फ्रिक्वेंसी के संबंध में किसी बदलाव में प्रदर्शित की जानी चाहिए।
12. स्कॉल मैसेजिंग केवल स्क्रीन के निचले भाग में उपलब्ध होनी चाहिए।
13. एसटीबी में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि फिंगर प्रिंटिंग कभी भी डिसेबल न हों।
14. सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो केवल इन्कोडर एंड में इन्सर्ट किया जाएगा।
बशर्त इन संशोधन विनियमों के लागू होने के बाद, स्थापित किए गए इनकोडर्स केवल इनकोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो को सपोर्ट करेंगे।

(ङ) सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी):

1. सभी एसटीबी में कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होना चाहिए।
2. एसटीबी हेड-एंड द्वारा इन्सर्ट किए गए कंडीशनल एक्सेस मैसेजों को डिफ्रिक्ट करने में समर्थ होने चाहिए।
3. एसटीबी को फिंगर प्रिंटिंग करने में समर्थ होना चाहिए। एसटीबी इन्टाइटलमेंट कंट्रोल मैसेज (ईसीएम) और इन्टाइटलमेंट मैनेजमेंट मैसेज (ईएमएम) आधारित फिंगरप्रिंटिंग को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए।
4. एसटीबी एकल रूप में हेड-एंड से एड्रेसेबल होना चाहिए।
5. एसटीबी हेड-एंड से मैसेज प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए।
6. मैसेज करेक्टर लंबाई कम से कम 120 करेक्टर की होगी।
7. इसमें ग्लोबल मैसेजिंग, ग्रुप मैसेजिंग और एकल एसटीबी मैसेजिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।
8. एसटीबी में फोर्सड फिंगर प्रिंटिंग डिस्प्ले सहित फोर्सड मैसेजिंग की क्षमता होनी चाहिए।
9. एसटीबी को लागू भारतीय मानक ब्यूरो का अनुपालन करने वाला होना चाहिए।
10. एसटीबी ओटीए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए ओवर द एयर के लिए एड्रेसेबल होना चाहिए।
11. कार्यक्रमों को रिकार्ड करने की सुविधा वाले एसटीबी में कंटेंट कॉपी प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होना चाहिए।

सुनील कुमार गुप्ता, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./272/19]

टिप्पणी 1 : मूल विनियम दिनांक 3 मार्च, 2017 को अधिसूचना संख्या 21-4/2016-बीएंडसीएस के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे।

टिप्पणी 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2019 के उद्देश्य और कारण स्पष्ट किए गए हैं।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भादूविप्रा ने 4 मई, 2016 को "एड्रसेबल प्रणाली के माध्यम से वितरित प्रसारण टीवी सेवाओं हेतु इंटरकनेक्शन फ्रेमवर्क" पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। इस परामर्श प्रक्रिया के बाद, 3 मार्च, 2017 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल प्रणाली) विनियम, 2017 (2017 का 1) (जिसे इसमें आगे इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 कहा गया है) की अधिसूचना जारी की गई थी।

2. अंकेक्षण नियमावली को तैयार करने के लिए किए गए परामर्श के दौरान, कुछ टिप्पणियों और प्रेक्षणों में इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III के कुछ मुद्दों को उठाया गया।

3. तदनुसार, 27 अगस्त, 2019 को मसौदा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल प्रणाली) (संशोधन) विनियम, 2019 (इसमें आगे जिसे मसौदा विनियम कहा गया है) जारी किए गए थे। इन मसौदा विनियमों द्वारा निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III में संशोधन किए गए हैं: —

- i. डिजिटल राइट मैनेजमेंट प्रणाली
- ii. सीएस और एसएमएस प्रणाली की ट्रांजेक्शनल क्षमता
- iii. फिंगरप्रिंटिंग-एसटीबी में विजिबल और कवर्ट फिंगरप्रिंटिंग के लिए सपोर्ट
- iv. सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो

4. हितधारकों से 9 सितंबर, 2019 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी। हितधारकों के अनुरोध पर, टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय सीमा 16 सितंबर, 2019 तक बढ़ाई गई थी। हितधारकों से बारह टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। इसके बाद, दिल्ली में 26 सितंबर, 2019 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में हितधारकों ने भाग लिया।

5. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने और इन-हाउस विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रसेबल प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2019 (इसमें आगे जिसे संशोधन विनियम कहा गया है) को अंतिम रूप दिया। आगे के पैराग्राफ में संशोधन विनियम के उद्देश्यों और कारणों के बारे में बताया गया है।

अंकेक्षण का स्कोप

6. मसौदा विनियम के अनुसार, वितरक द्वारा कराई जाने वाली वार्षिक अंकेक्षण में इस अनुसूची के अनुपालन में अंकेक्षण और सब्सक्रिप्शन अंकेक्षण शामिल होगा।

7. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, कुछ हितधारकों ने इस खंड में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया। सुझाव के अनुसार, वितरक द्वारा कराई जाने वाली वार्षिक अंकेक्षण में इस अनुसूची के अनुपालन में अंकेक्षण और सब्सक्रिप्शन अंकेक्षण शामिल होगा। इसके अलावा, कुछ हितधारकों ने इस खंड के लिए स्पष्टीकरण भी दिए कि इंटरकनेक्शन समझौते के प्रावधानों के साथ पठित अंकेक्षण नियमावली में दिए गए विस्तृत अंकेक्षण पद्धति/चरणों का पालन करना आवश्यक है, पैनेलबद्ध अंकेक्षणों की डीपीओ या प्रसारक द्वारा कराई जाने वाली अंकेक्षण में डीपीओ की प्रणालियों के समस्त एवं अपरिवर्तित डेटा और लॉग्स तक पहुंच होगी। अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार होने और अंकेक्षणों द्वारा जारी किए जाने तक, डीपीओ द्वारा सीएस और एसएमएस सर्वर के डेटा की किसी भी कारण से फिल्टरिंग नहीं की जानी चाहिए।

8. प्राधिकरण का मानना है कि स्पष्टीकरण और अन्य टिप्पणियों के रूप में प्रस्तावित मुद्दों पर अंकेक्षण नियमावली से संबंधित परामर्श प्रक्रिया में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। इस खंड पर हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण का मानना है कि वितरक द्वारा कराई जाने वाली वार्षिक अंकेक्षण में इस अनुसूची के अनुपालन में अंकेक्षण और सब्सक्रिप्शन अंकेक्षण शामिल होगी।

अंकेक्षण की शड्यूलिंग

9. मसौदा अंकेक्षण नियमावली पर टिप्पणियों और चर्चा के दौरान, कई हितधारकों ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण को डीपीओ के लिए अंकेक्षण की अनुसूची निर्दिष्ट करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंकेक्षण प्रभावी ढंग से और समय पर कराई गई है। इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियम 15 के खंड (1) के अनुसार, डीपीओ को वर्ष में एक बार अंकेक्षण करानी होगी। हितधारक चाहते हैं कि प्राधिकरण लेखा परीक्षकों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए अंकेक्षण अनुसूची को निर्दिष्ट करें और यह भी कि यदि सभी डीपीओ अपने सिस्टम को किसी वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अंकेक्षण कराने का विकल्प चुनते हैं तो इससे गंभीर क्षमता अवरोध उत्पन्न हो जाएगा।

10. इसके विपरीत, अधिकांश डीपीओ का मानना था कि जिम्मेदार हितधारक होने के नाते, वे अपने सिस्टम का ठीक से और नियमों के अनुपालन में समयबद्ध तरीके से अंकेक्षण करवाएंगे। फ्रेमवर्क के अनुसार, वर्तमान और वैध अंकेक्षण अनुपालन बनाए रखने की जिम्मेदारी वितरकों की है। डीपीओ द्वारा की गई कोई भी चूक कई प्रसारकों के फॉलोअप और अंकेक्षण के अधीन होगी। इस प्रकार, फ्रेमवर्क में डीपीओ के साथ-साथ प्रसारकों के हित में पर्याप्त जांच और संतुलन का प्रावधान किया गया है।

11. डीपीओ द्वारा कराई गई दो अंकेक्षणों के बीच के अंतर के संबंध में एक और तर्क है। भादूविप्रा को प्राप्त टिप्पणियों में से एक यह थी कि डीपीओ के लिए लगातार दो महीनों में दो अलग-अलग कैलेंडर वर्षों की अंकेक्षण शडयूल करना संभव है। पहला वर्तमान वर्ष के दिसंबर में और दूसरा अगले कैलेंडर वर्ष के जनवरी में। ऐसे काल्पनिक मामलों में, वितरक की प्रणालियां 23 माह की लंबी अवधि के लिए अंकेक्षण के दायरे से बाहर रहेंगी। चूंकि नए फ्रेमवर्क के तहत विश्वास आधारित व्यवस्था बनाने में अंकेक्षण एक महत्वपूर्ण आधार का काम करती है इसलिए ड्राफ्ट विनियमों में प्रावधान है कि वितरक द्वारा अंकेक्षण इस तरह से शडयूल की जाएगी कि दो वर्षों की अंकेक्षण के बीच कम से कम छह माह का अंतराल हो।

12. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, अधिकांश हितधारकों ने इस खंड को शामिल करने का समर्थन किया है। हालांकि, कुछ हितधारकों ने इस खंड में कुछ और जोड़ने का सुझाव दिया। उनके अनुसार, प्रस्तावित संशोधन की शब्दावली में भ्रमात्मक स्थिति का ध्यान रखा गया है जिसमें डीपीओ लगातार दो महीनों (पहले कैलेंडर वर्ष का दिसंबर और दूसरे कैलेंडर वर्ष का जनवरी) में अंकेक्षण कराता है। हालांकि, इसमें अन्य अवांछनीय स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है जिसमें डीपीओ पहले कैलेंडर वर्ष के जनवरी में अंकेक्षण कराता है और फिर अगले कैलेंडर वर्ष के दिसंबर में अंकेक्षण कराता है यानी दो लगातार अंकेक्षण के बीच 23 महीने का अंतर है। इन हितधारकों का मत है कि यदि इतने लंबे अंतराल को अनुमति दी जाती है तो यह राजस्व आश्वासन के संबंध में प्रसारकों के हितों के खिलाफ होगा और सुझाव दिया कि दो लगातार कैलेंडर वर्षों की अंकेक्षण के बीच 12 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

13. हितधारकों द्वारा दिए गए सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण का मत है कि डीपीओ द्वारा कराई जाने वाली दो वार्षिक अंकेक्षण के बीच क्रमशः 6 और 18 महीने का न्यूनतम और अधिकतम अंतराल होना चाहिए। प्राधिकरण का मानना है कि लगातार दो कैलेंडर वर्षों की अंकेक्षण के बीच 18 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

14. इसके अलावा, कुछ हितधारकों ने यह मुद्दा उठाया कि प्राधिकरण को ऐसे डीपीओ से निपटने के लिए उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करना चाहिए जो नियामक प्रावधानों खासकर समयसीमा का पालन नहीं करते हैं। समुचित विचार के बाद, प्राधिकरण ने एक कैलेंडर वर्ष में अंकेक्षण न कराने वाले टेलीविजन चैनलों के वितरक के लिए वित्तीय निरुत्साहन का निर्धारण किया है। एक वर्गीकृत पैमाने पर वित्तीय निरुत्साहन का प्रस्ताव किया गया है। यदि नियत तारीख तक अंकेक्षण नहीं कराई जाती है, तो टेलीविजन चैनलों के वितरक पहले तीस दिनों की देरी के लिए प्रति दिन एक हजार रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तीस दिनों से अधिक देरी के मामले में, वित्तीय निरुत्साहन बढ़ेगा और पहले तीस दिनों के बाद यह 2000 रुपये प्रतिदिन होगा। इसके अलावा, प्राधिकरण मानता है कि अधिकतम वित्तीय निरुत्साहन की एक ऊपरी सीमा होनी जरूरी है। इसलिए, प्राधिकरण ने उल्लंघन/विलंब के लिए दो लाख रुपये (अधिकतम दो सौ हजार रुपये) की अधिकतम सीमा निर्धारित की है।

सीएस और एसएमएस सिस्टम की ट्रांजेक्शनल क्षमता

15. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III की धारा ए के पैरा 8 के अनुसार, 'सीएस और एसएमएस को 24 घंटे के भीतर वितरक के उपभोक्ता आधार के कम से कम 10 प्रतिशत के एसटीबी या सेवाओं को सक्रिय या निष्क्रिय करने में समर्थ होना चाहिए।'

16. जब की यह आवश्यकता उचित लगती है, यह कुछ बड़े डीपीओ की ओर से अनपेक्षित निवेश करता है। अधिकांश डीटीएच सेवा प्रदाताओं और शीर्ष चार से पांच एमएसओ के लिए यह मुद्दा वास्तव में चिंताजनक बन जाता है। इन ऑपरेटरों में से प्रत्येक के पास पांच मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। इसलिए, उन्होंने प्राधिकरण से इस उच्चतम सीमा की समीक्षा करने का अनुरोध किया था।

17. आमतौर पर, इन बड़े ऑपरेटरों को दैनिक आधार पर अपने 1 प्रतिशत से अधिक सक्रिय ग्राहकों के सक्रिय/निष्क्रिय/पुनः कॉन्फिगर करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए, ऑपरेटरों ने निवेदन किया है कि सक्रियण/निष्क्रियण के 10 प्रतिशत को पूरा करने के लिए उपकरण लगाने का प्रावधान करना अनुचित है।

18. हालांकि, कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया है कि वर्तमान में अधिकांश ग्राहक मासिक प्री-पेड पैकेज वाले हैं और औसतन हर ग्राहक को हर महीने एक बार भुगतान/रिचार्ज कराना आवश्यक है और महीने में एक बार एसएमएस स्तर पर कॉन्फिगर करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, ऐसे हितधारकों ने तर्क दिया है कि सीएस/एसएमएस की न्यूनतम 3.3 प्रतिशत क्षमता आवश्यक है। मसौदा विनियम में उल्लेख किया गया है कि सीएस और एसएमएस को 24 घंटे के भीतर वितरक के कम से कम पांच प्रतिशत (5 प्रतिशत) ग्राहक की सेवाओं या एसटीबी को सक्रिय या निष्क्रिय करने में सक्षम होना चाहिए।

19. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, कुछ हितधारकों ने संशोधन का समर्थन किया। एक हितधारक ने कहा कि एमएसओ/डीपीओ को बिना किसी समस्या के एसटीबी को सक्रिय करने के लिए अपने सिस्टम की क्षमता बढ़ानी चाहिए। एमएसओ/डीपीओ की कम ट्रांजेक्शनल क्षमता के कारण ग्राहकों और प्रसारकों को नुकसान होता है। एक अन्य हितधारक ने सुझाव दिया कि ग्राहक आधार सीएस और एसएमएस की क्षमता का आकलन करने के लिए उपयुक्त मानदंड नहीं हो सकता है, और मौजूदा फ्रेमवर्क में कोई एकल ग्राहक चैनल के सक्रियण/निष्क्रियण, रिचार्ज के संदर्भ में एक से अधिक ट्रांजेक्शन जनरेट कर सकता है, इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रांजेक्शन की कुल मात्रा के संदर्भ में 5 प्रतिशत के मापदंड की समीक्षा की जानी चाहिए।

20. परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सभी टिप्पणियों और आंतरिक विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण का मत है कि सीएस और एसएमएस को 24 घंटे के भीतर वितरक के कम से कम पांच प्रतिशत (5 प्रतिशत) ग्राहकों की सेवाओं या एसटीबी को सक्रिय या निष्क्रिय करने में सक्षम होना चाहिए।

फ़िगरप्रिंटिंग – एसटीबी में विजिबल और कवर्ट फ़िगरप्रिंटिंग का सपोर्ट

21. सभी एसटीबी पर विजिबल और कवर्ट फ़िगरप्रिंटिंग की उपलब्धता के संबंध में समस्या हैं। इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार, स्थापित सभी एसटीबी दोनों प्रकार की फ़िगरप्रिंटिंग मुहैया नहीं कराते हैं। इंटरकनेक्शन विनियम 2017 से पहले, विजिबल फ़िगरप्रिंटिंग वाले एसटीबी नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त थे। इसलिए, कुछ वितरकों ने उल्लेख किया है कि वर्ष 2017 से पहले स्थापित सेट-टॉप बॉक्स कवर्ट फ़िगरप्रिंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) इंटरकनेक्शन (डिजिटल एड्रैसेबल केबल टीवी सिस्टम) विनियम, 2012 में इसे अनिवार्य नहीं किया गया था। बीआईएस मानकों में भी विजिबल और कवर्ट, दोनों फ़िगरप्रिंटिंग को अनिवार्य नहीं किया गया था।

22. कुछ वितरकों ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह उपर्युक्त विसंगतियों के दृष्टिगत इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III की समीक्षा करें। इन हितधारकों का मानना है कि इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में निर्दिष्ट कवर्ट फ़िगरप्रिंट की प्रणाली वाली अपेक्षा केवल उन सेट-टॉप बॉक्स पर लागू होनी चाहिए, जो इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 के लागू होने के बाद स्थापित किए गए हैं न कि इससे पहले स्थापित बॉक्स पर। कुछ हितधारकों का यह मानना है कि एसटीबी की औसत आयु लगभग 3 वर्ष है, इसको देखते हुए, पुराने एसटीबी अगले दो वर्षों के भीतर स्वतः सेवा से बाहर हो जाएंगे।

23. विसंगति को ध्यान में रखते हुए, मसौदा विनियमों में उल्लेख किया गया है कि इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के लागू होने के बाद, स्थापित एसटीबी के लिए केवल कवर्ट फ़िगरप्रिंटिंग को सपोर्ट करने की अनिवार्यता होनी चाहिए।

24. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि एक समय सीमा भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए। कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि स्थापित सभी एसटीबी 1 जुलाई, 2020 तक सभी पे चैनलों के लिए कवर्ट फ़िगरप्रिंटिंग को सपोर्ट करेंगे। एक हितधारक के अनुसार, कवर्ट फ़िगरप्रिंटिंग ग्राउंड पर चोरी का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसे पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए। भादूविप्रा को डीपीओ को अपनी मौजूदा तकनीकों/एसटीबी को कवर्ट फ़िगरप्रिंटिंग तकनीक से बदलने के लिए एक समय सीमा का निर्धारण करना चाहिए।

25. सभी टिप्पणियों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण का मानना है कि इन संशोधन विनियमों के लागू होने के बाद लगाए गए एसटीबी केवल कवर्ट फ़िगर प्रिंटिंग को सपोर्ट करेंगे। एसटीबी के जीवन-काल को देखते हुए, यह स्वाभाविक है कि निश्चित रूप से नेटवर्क में सभी एसटीबी विजिबल और कवर्ट फ़िगरप्रिंटिंग, दोनों के अनुरूप हो जाएंगे। इसलिए, इसके लिए किसी विशिष्ट विनियम को शामिल करना जरूरी नहीं है।

डीपीओ द्वारा नेटवर्क लोगो की वॉटरमार्किंग

26. डीपीओ द्वारा सभी सिग्नलस के संयोजन से पहले इनकोडर छोर पर 'वॉटरमार्किंग' लोगो अंतःस्थापित किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, एक डीपीओ एसटीबी में दिए गए अपने मिडलवेयर के माध्यम से 'वाटरमार्किंग' प्रस्तुत कर सकता है।

27. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III के भाग बी के पैरा 13 के अनुसार, 'सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो केवल इनकोडर छोर पर अंतःस्थापित किया जाएगा'।

28. कई डीपीओ ने भादूविप्रा से अनुरोध किया है कि 'वॉटरमार्किंग' नेटवर्क लोगो इनकोडर द्वारा भी अंतःस्थापित किया जा सकता है, केवल तब जब इनकोडर्स में यह सुविधा होगी। हालांकि, ऐसे एमएसओ द्वारा वर्तमान में स्थापित किए गए कई इनकोडर उनकी लीगेसी प्रणाली का हिस्सा हैं और इसमें वॉटरमार्किंग लोगो लगाने का प्रावधान नहीं है।

29. इस मुद्दे और लीगेसी प्रणालियों पर लागत के निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए, मसौदा विनियमों में उल्लेख किया गया है कि इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के लागू होने के बाद, स्थापित इनकोडर के लिए केवल इनकोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो का सपोर्ट करने की अनिवार्यता होनी चाहिए।

30. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि इसके लिए कोई समय सीमा होनी चाहिए। कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि स्थापित सभी इनकोडर 1 जुलाई, 2020 तक इनकोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो को सपोर्ट करेंगे। एक हितधारक के अनुसार, इंडस्ट्री में ऑनलाइन चोरियां बढ़ी हैं। वॉटरमार्किंग लोगो की अनुपस्थिति में, चोरी की घटनाओं में कई गुना वृद्धि होने की संभावना है। वॉटरमार्किंग खंड को बनाए रखने का प्रावधान होना चाहिए और वर्तमान में, बाजार में मौजूद इनकोडर को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे उन इनकोडर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, जिनमें पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग लोगो का सपोर्ट करने की सुविधा हो, ताकि चोरी पर अंकुश लगाया जा सके।

31. सभी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण का मानना है कि इन संशोधन विनियमों के लागू होने के बाद, स्थापित किए गए इनकोडर्स केवल इनकोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो को सपोर्ट करेंगे।

डिजिटल राइट मैनेजमेंट प्रणाली (डीआरएम)

32. डीआरएम, डिजिटल मीडिया के लिए कॉपीराइट सुरक्षा के लिए एक उचित दृष्टिकोण है। डीआरएम का उद्देश्य डिजिटल मीडिया के अनधिकृत पुनर्वितरण को रोकना और उन तरीकों को पर रोक लगाना है, जिनके द्वारा उपभोक्ता खरीदी गई सामग्री को कॉपी कर सकते हैं। डीआरएम उत्पादों को

व्यावसायिक रूप से बेची गई सामग्री की ऑनलाइन चोरी में तेज वृद्धि को रोकने के लिए बनाया गया था, जो सहकर्मी से सहकर्मी फाइल विनियम कार्यक्रमों के व्यापक उपयोग के माध्यम से विकसित हुआ था। आमतौर पर, डीआरएम को कोड लगाके लागू किया जाता है जो कॉपी करने से रोकता है, एक समय अवधि निर्दिष्ट करता है जिसमें सामग्री को एक्सेस किया जा सकता है या मीडिया पर स्थापित किए जा सकने वाले उपकरणों की संख्या को सीमित करता है। डीआरएम प्रौद्योगिकी पहली जगह में सामग्री चोरी करने को असंभव बनाती है, यह तथ्य के बाद ऑनलाइन चोरों को पकड़ने की हिट-एंड-मिस योजनाओं की तुलना में इस समस्या के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण है।

33. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III डीआरएम आधारित प्रणालियों की अपेक्षाओं/विशिष्टियों के लिए प्रावधान नहीं करती है। प्राधिकरण को अंकेक्षण नियमावली पर अपने परामर्श के दौरान, प्रतिक्रिया मिली कि इसके लाभ के कारण आईपीटीवी आधारित डीपीओ डीआरएम प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। यह आवश्यक है कि अंकेक्षण के दायरे में डीआरएम आधारित नेटवर्क को शामिल करें और ऐसे ऑपरेटरों को सक्षम करने के लिए प्रावधान करें। तदनुसार, मसौदा विनियमों में अनुसूची III में डीआरएम विशिष्टियां शामिल की गई थी।

34. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों से कई टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त किए। कई हितधारकों द्वारा कई संशोधन/परिवर्धन प्रस्तावित किए गए थे। इसलिए, प्राधिकरण का मत है कि डीआरएम के लिए सिस्टम अपेक्षाओं पर एक अलग परामर्श पत्र में विचार किया जाएगा।

अन्य मामले

35. अंकेक्षण के स्कोप और शडयूलिंग, सीएस और एसएमएस सिस्टम की ट्रांजेक्शनल क्षमता, कवर्ट फिंगरप्रिंटिंग, वॉटरमार्किंग लोगो और डीआरएम से संबंधित मुद्दों पर इंटरकनेक्शन विनियम की अनुसूची III में प्रस्तावित संशोधनों के अलावा, प्राधिकरण को कई हितधारकों से अनुसूची III के अन्य खंडों में संशोधन के संबंध में बड़ी संख्या में टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। कई हितधारकों ने अनुसूची III में संशोधन के सुझाव दिए हैं। अनुसूची III में शामिल किए जाने के लिए अतिरिक्त खंडों/धाराओं के संबंध में भी सुझाव प्राप्त किए गए थे।

36. प्राधिकरण का मत है कि इनमें से अधिकांश सुझाव अंकेक्षण प्रक्रिया से संबंधित हैं और अंकेक्षण नियमावली की परामर्श प्रक्रिया के दौरान लम्बी चर्चा की गई थी। इसके अलावा डीआरएम से संबंधित मामलों पर अलग परामर्श प्रक्रिया की जरूरत है। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में अन्य मामलों पर बिंदूसार चर्चा की गई है।

37. इसके अतिरिक्त, दिनांक 20.09.2019 को मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) से प्राप्त अभ्यावेदन, जिसमें उन्होंने ट्राई को सूचित किया है कि इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की धारा 15 के अंतर्गत अंकेक्षण कराने में बीईसीआईएल का नाम नहीं बताया गया है, जबकि इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियम 10 ने अंकेक्षण का संचालन करने के लिए बीईसीआईएल या ट्राई द्वारा पैनल में रखे गए अंकेक्षकों में से किसी से अनिवार्य किया है। बीईसीआईएल ने उल्लेख किया है कि इसको देखते हुए कई एमएसओ जो विनियम 15 के अंतर्गत अंकेक्षण को कराने में बीईसीआईएल की सेवाएँ लेना चाहते हैं, ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। बीईसीआईएल नियमित रूप से और साथ ही माननीय टीडीएसएटी द्वारा निर्देशित अंकेक्षण में ट्राई के 2004, 2009 और 2012 के पहले के इंटरकनेक्शन विनियमों के अंतर्गत तकनीकी के साथ-साथ वाणिज्यिक अंकेक्षण भी कर रहा है जिसमें कमर्शियल के साथ-साथ तकनीकी अंकेक्षण भी शामिल हैं। बीईसीआईएल ने आगे उल्लेख किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि विनियम 15 में, बीईसीआईएल के नाम का उल्लेख अनजाने में छोड़ दिया गया है। इसलिए, बीईसीआईएल ने अनुरोध किया कि 10 वर्षों से इन अंकेक्षण के संचालन में बीईसीआईएल के विशाल अनुभव और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए ट्राई के सूचीबद्ध अंकेक्षकों के अलावा, उन्हें विनियम 15 के अंतर्गत वाणिज्यिक अंकेक्षण आयोजित करने के लिए भी नामांकित किया जाना चाहिए। मसौदा विनियमों पर आयोजित ओएचडी में बेसिल ने इस मुद्दे को भी उठाया। ओएचडी के दौरान, प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर सभी हितधारकों से परामर्श किया, और यह महसूस किया कि बीईसीआईएल का नाम विनियम 15 में शामिल किया जा सकता है।

38. तदनुसार, 3 मार्च, 2017 के इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में संशोधन किया गया है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2019

THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES INTERCONNECTION (ADDRESSABLE SYSTEMS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

(7 of 2019)

F. No. 21-6/2019-B&CS.—In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Central Government, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No. 39, —

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 11 and proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, and

(b) published under notification No. S.O.44 (E) and 45 (E) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,—

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (1 of 2017), namely: -

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Amendment) Regulations, 2019 (7 of 2019).

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 15 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as the principal regulations) – (a) for first proviso to sub-regulation (1), the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that the Authority may empanel auditors for the purpose of such audit and it shall be mandatory for every distributor of television channels to cause audit, under this sub-regulation, from M/s Broadcast Engineering Consultants India limited, or any of such empanelled auditors.”;

(b) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(1 A) If any distributor fails to cause audit once in a calendar year of its subscriber management system, conditional access system and other related systems, as specified under sub-regulation (1), it shall, without prejudice to the terms and conditions of its license or permission or registration, or the Act or rules or regulations or order made or direction issued thereunder, be liable to pay, by way of financial disincentive, an amount of rupees one thousand per day for default up to thirty days beyond the due date and an additional amount of rupees two thousand per day in case the default continues beyond thirty days from the due date, as the Authority may, by order, direct:

Provided that the financial disincentive levied by the Authority under this sub-regulation shall in no case exceed rupees two lakhs:

Provided further that no order for payment of any amount by way of financial disincentive shall be made by the Authority unless the distributor, has been given a reasonable opportunity of representation against the contravention of the regulations observed by the Authority.”;

(c) for first proviso to sub-regulation (2), the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that the Authority may empanel auditors for the purpose of such audit and it shall be mandatory for every broadcaster to cause audit, under this sub-regulation, from M/s Broadcast Engineering Consultants India limited, or any of such empanelled auditors.”

3. For Schedule III of the principal regulations, the following schedule shall be substituted, namely:-

“Schedule III

(Refer sub-regulation (6) of the regulation 10 and regulation 15)

Scope and Scheduling of Audit

(A) Scope: The annual Audit caused by Distributor shall include the Audit to validate compliance with this Schedule and the Subscription Audit, as provided for in these regulations.

(B) Scheduling: The annual Audit as caused by Distributor under regulation 15 (1) shall be scheduled in such a manner that there is a gap of at-least six months between the audits of two consecutive calendar years. Further, there should not be a gap of more than 18 months between audits of two consecutive calendar years.

Addressable Systems Requirements

(C) **Conditional Access System (CAS) and Subscriber Management System (SMS):**

1. The distributor of television channels shall ensure that the current version of the CAS, in use, do not have any history of hacking.

Explanation: A written declaration available with the distributor from the CAS vendor, in this regard, shall be construed as compliance of this requirement.

2. The SMS shall be independently capable of generating, recording, and maintaining logs, for the period of at least immediate preceding two consecutive years, corresponding to each command executed in the SMS including but not limited to activation and deactivation commands.
3. It shall not be possible to alter the data and logs recorded in the CAS and the SMS.
4. The distributor of television channels shall validate that the CAS, in use, do not have facility to activate and deactivate a Set Top Box (STB) directly from the CAS terminal. All activation and deactivation of STBs shall be done with the commands of the SMS.
5. The SMS and the CAS should be integrated in such a manner that activation and deactivation of STB happen simultaneously in both the systems.

Explanation: Necessary and sufficient methods shall be put in place so that each activation and deactivation of STBs is reflected in the reports generated from the SMS and the CAS terminals.

6. The distributor of television channels shall validate that the CAS has the capability of upgrading STBs over-the-air (OTA), so that the connected STBs can be upgraded.
7. The fingerprinting should not get invalidated by use of any device or software.
8. The CAS and the SMS should be able to activate or deactivate services or STBs of at least Five percent (5%) of the subscriber base of the distributor within 24 hours.
9. The STB and Viewing Card (VC) shall be paired from the SMS to ensure security of the channel.
10. The CAS and SMS should be capable of individually addressing subscribers, for the purpose of generating the reports, on channel by channel and STB by STB basis.
11. The SMS should be computerized and capable of recording the vital information and data concerning the subscribers such as:
 - (a) Unique customer identification (ID)
 - (b) Subscription contract number
 - (c) Name of the subscriber
 - (d) Billing address
 - (e) Installation address
 - (f) Landline telephone number
 - (g) Mobile telephone number
 - (h) E-mail address
 - (i) Channels, bouquets and services subscribed
 - (j) Unique STB number
 - (k) Unique VC number.
12. The SMS should be capable of:
 - (a) Viewing and printing of historical data in terms of the activations and the deactivations of STBs.
 - (b) Locating each and every STB and VC installed.
 - (c) Generating historical data of changes in the subscriptions for each subscriber and the corresponding source of requests made by the subscriber.
13. The SMS should be capable of generating reports, at any desired time about:
 - (a) The total number of registered subscribers.
 - (b) The total number of active subscribers.
 - (c) The total number of temporary suspended subscribers.
 - (d) The total number of deactivated subscribers.
 - (e) List of blacklisted STBs in the system.
 - (f) Channel and bouquet wise monthly subscription report in the prescribed format.
 - (g) The names of the channels forming part of each bouquet.
 - (h) The total number of active subscribers subscribing to a particular channel or bouquet at a given time.
 - (i) The name of a-la carte channel and bouquet subscribed by a subscriber.
 - (j) The ageing report for subscription of a particular channel or bouquet.
14. The CAS shall be independently capable of generating, recording, and maintaining logs, for the period of at least immediate preceding two consecutive years, corresponding to each command executed in the CAS including but not limited to activation and deactivation commands issued by the SMS.

15. The CAS shall be able to tag and blacklist VC numbers and STB numbers that have been involved in piracy in the past to ensure that such VC or the STB cannot be re-deployed.
16. It shall be possible to generate the following reports from the logs of the CAS:
 - (a) STB-VC Pairing / De-Pairing
 - (b) STB Activation / De-activation
 - (c) Channels Assignment to STB
 - (d) Report of the activations or the deactivations of a particular channel for a given period.
17. The SMS shall be capable of generating bills for each subscriber with itemized details such as the number of channels subscribed, the network capacity fee for the channels subscribed, the rental amount for the customer premises equipment, charges for pay channel and bouquet of pay channels along with the list and retail price of corresponding pay channels and bouquet of pay channels, taxes etc.
18. The distributor shall ensure that the CAS and SMS vendors have the technical capability in India to maintain the systems on 24x7 basis throughout the year.
19. The distributor of television channels shall declare the details of the CAS and the SMS deployed for distribution of channels. In case of deployment of any additional CAS/ SMS, the same should be notified to the broadcasters by the distributor.
20. Upon deactivation of any subscriber from the SMS, all programme/ services shall be denied to that subscriber.
21. The distributor of television channels shall preserve unedited data of the CAS and the SMS for at least two years.

(D) Fingerprinting: -

1. The distributor of television channels shall ensure that it has systems, processes and controls in place to run finger printing at regular intervals.
2. The STB should support both visible and covert types of finger printing.
Provided that only the STB deployed after coming into effect of these Amendment regulations shall support the covert finger printing.
3. The fingerprinting should not get invalidated by use of any device or software.
4. The finger printing should not be removable by pressing any key on the remote of STB.
5. The finger printing should be on the top most layer of the video.
6. The finger printing should be such that it can identify the unique STB number or the unique VC number.
7. The finger printing should appear on the screens in all scenarios, such as menu, Electronic Programme Guide (EPG), Settings, blank screen, and games etc.
8. The location, font colour and background colour of fingerprint should be changeable from head end and should be random on the viewing device.
9. The finger printing should be able to give the numbers of characters as to identify the unique STB and/or the VC.
10. The finger printing should be possible on global as well as on the individual STB basis.
11. The overt finger printing should be displayed by the distributor of television channels without any alteration with regard to the time, location, duration and frequency.
12. Scroll messaging should be only available in the lower part of the screen.
13. The STB should have a provision that finger printing is never disabled.
14. The watermarking network logo for all pay channels shall be inserted at encoder end only.
Provided that only the encoders deployed after coming into effect of these Amendment regulations shall support watermarking network logo for all pay channels at the encoder end.

(E) Set Top Box (STB): -

1. All STBs should have a Conditional Access System.
2. The STB should be capable of decrypting the Conditional Access messages inserted by the Head-end
3. The STB should be capable of doing finger printing. The STB should support both Entitlement Control Message (ECM) and Entitlement Management Message (EMM) based fingerprinting.
4. The STB should be individually addressable from the Head-end.

5. The STB should be able to receive messages from the Head-end.
6. The messaging character length should be minimal 120 characters.
7. There should be provision for global messaging, group messaging and the individual STB messaging.
8. The STB should have forced messaging capability including forced finger printing display.
9. The STB must be compliant to the applicable Bureau of Indian Standards.
10. The STBs should be addressable over the air to facilitate OTA software upgrade.
11. The STBs with facilities for recording the programs shall have a copy protection system.

SUNIL KUMAR GUPTA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./272/19]

Note. 1: The principal regulations were published in the Gazette of India, extraordinary, Part III, Section 4 vide notification No. 21-4/2016-B&CS dated the 3rd March, 2017.

Note. 2: The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Amendment) Regulations, 2019.

Explanatory Memorandum

A consultation paper on “Interconnection framework for Broadcasting TV Services distributed through Addressable Systems” was issued by TRAI on 4 May, 2016. This consultation process resulted in notification of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (1 of 2017) dated the 3rd March, 2017 [hereinafter referred to as Interconnection Regulations 2017].

2. During the consultation undertaken to prepare the Audit Manual certain comments and observations reflect some issues in the Schedule III of the Interconnection Regulations 2017.

3. Accordingly, Draft Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Amendment) Regulations, 2019 [hereinafter referred to as the Draft Regulations] was issued on 27 August, 2019. These Draft Regulations amended Schedule III of the Interconnection Regulations 2017, on the following issues: -

- i. Digital Rights Management Systems
- ii. Transactional capacity of CAS and SMS system
- iii. Fingerprinting – Support for Visible and Covert fingerprinting in STBs
- iv. Watermarking network logo for all pay channels

4. The comments of the stakeholders were invited by 9 September, 2019. On request of stakeholders, the deadline to submit the comments was extended till 16 September, 2019. Twelve comments were received from stakeholders. Subsequently, an Open House Discussion (OHD) was held on 26 September, 2019 in Delhi, which was attended by a large number of stakeholders.

5. After taking into consideration the comments received from the stakeholders and in-house analysis, the Authority finalized the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Amendment) Regulations, 2019 [hereinafter referred to as the Amendment Regulations]. The subsequent paragraphs explain the objects and reasons of the Amendment Regulations.

Scope of Audit

6. Draft Regulations specified that the annual Audit caused by Distributor shall include the Audit in compliance with this Schedule and the Subscription Audit.

7. During the consultation process, a few stakeholders suggested some modifications in this clause. According to the suggestion, the annual Audit caused by Distributor shall include the Audit to validate compliance with this Schedule and the Subscription Audit. In addition, some stakeholders also proposed explanation to this clause that detailed audit methodology / steps provided in Audit Manual read with provisions of interconnection agreement are required to be followed, the empanelled auditor shall have the right to seek / obtain directly any data / information / declaration from CAS / DRM and SMS vendors regarding audit requirements, empanelled auditor shall have access to complete and unaltered data & logs of the DPO's systems in the audits caused either by DPO or by Broadcaster, there should not be

any filtering of data by DPO from CAS and SMS server for any reason whatsoever till the Audit report is prepared and released by the Auditor.

8. The Authority is of the view that the issues proposed as explanation and other comments have already been discussed at length in the consultation process related to audit manual. Keeping in view all the comments and suggestions received from the stakeholders on this clause, the authority is of the view that the annual Audit caused by Distributor shall include the Audit to validate compliance with this Schedule and the Subscription Audit.

Scheduling of Audit

9. During the comments and discussion on the Draft Audit Manual many stakeholders have suggested that the authority should specify the schedule of audit for DPOs to ensure that the audit is held effectively and in a timely manner. Clause (1) of regulation 15 of Interconnection Regulations 2017 provides that a DPO will get audit completed once every year. Stakeholders that are desirous that the Authority may specify the audit schedule refer to the limited availability of auditors and also that if all DPOs chose to get their systems audited during the last quarter of a year, there will be a severe capacity constraint.

10. On the contrary, most of the DPOs have averred that being responsible stakeholders, they will get their systems audited properly and in a time-bound manner in compliance with the regulations. As per the framework, it is incumbent upon distributors to maintain a current and valid audit compliance. Any slippage by DPO will entail follow up and audits by multiple broadcasters. The framework, therefore, has sufficient checks and balances in the interest of DPOs as well as broadcasters.

11. There is another argument as regards the gap between the two audits caused by the DPOs. One of the comments received by TRAI was that it is possible for a DPO to schedule audits of two different calendar years in consecutive months. That is first one in December of current year and next one in January of next calendar year. In such hypothetical cases, the systems of the distributor will remain out of the ambit of audit for a long period of 23 months. Given that audit is an important foundation in establishing the trust-based regime under the new regulatory framework, therefore the Draft Regulations mentioned that the annual Audit caused by Distributor shall be scheduled in such a manner that there is a gap of at-least six months between the audits of two consecutive calendar years.

12. During the consultation process, most of the stakeholders favoured the inclusion of this clause. However, some stakeholders suggested an addition to this clause. According to them, wording in proposed amendment takes care of erroneous situation where DPO causes audits in two consecutive months (December of first calendar year and January of second calendar year). However, this does not take care of the other undesirous situation where DPO causes audit in January of first calendar year and then causes next audit in December of second calendar year i.e. there is a gap of 23 months between two consecutive audits. These stakeholders opined that this long gap if allowed is detrimental to the interest of broadcasters for revenue assurance and proposed that there should not be a gap of more than 12 months between audits of two consecutive calendar years.

13. Keeping in view all the suggestions given by the stakeholders the Authority is of the opinion that there should be a minimum and a maximum gap of 6 and 18 months respectively, between two annual audits caused by a DPO. The Authority is of the view that there should not be a gap of more than 18 months between audits of two consecutive calendar years.

14. Further, quite a few stakeholders have raised the issue that the Authority should incorporate appropriate provisions for dealing with such DPOs who do not comply with regulatory provisions, especially when it comes to adherence to timelines. After due consideration, the Authority has prescribed levying of financial disincentives on the distributor of television channels for not causing an audit in a calendar year. The financial disincentive is proposed on a graded scale. That is if the audit is not caused by the due date, then the distributor of television channels will be liable to pay an amount of rupees one thousand per day for the delay of first thirty days. In case of delay beyond thirty days, the financial disincentive will increase and will be @Rs. 2000/- per additional day beyond first thirty days. In addition, the Authority considers that the maximum financial disincentive may be restricted to an upper limit. Therefore, the Authority has prescribed a maximum limit of Rs Two Lakhs (Rs. Two Hundred Thousand) only per instance of violation/delay.

Transactional capacity of CAS and SMS systems

15. Para 8 of Section A of the Schedule III of the Interconnection Regulations 2017 specifies that, 'The CAS and the SMS should be able to activate or deactivate services or STBs of at least 10% of the subscriber base of the distributor within 24 hours.'

16. While the requirement seems as reasonable, this puts an unwarranted investment on part of certain large DPOs. The issue becomes really alarming for most of the DTH service providers and top four to five MSOs. Each one of these operators have a subscriber base of more than five million customers. Hence, they had requested the Authority to review this threshold limit.

17. In general, these large operators do not need to activate/ deactivate/ re-configure more than 1 % of their active subscribers on everyday basis. Therefore, the operators have represented that prescribing to deploy equipment to cater to 10% of activation/ deactivation is uncalled for.

18. However, some stakeholders have suggested that most of the subscribers are on monthly pre-paid packages these days and by the law of averages every customer is required to pay/ recharge once every month and may require to be configured at the SMS level once every month. Therefore, such stakeholders have argued that a minimum of 3.3 % capacity of CAS/ SMS is necessary. The Draft Regulations mentioned that the CAS and the SMS should be able to activate or deactivate services or STBs of at least Five percent (5%) of the subscriber base of the distributor within 24 hours.

19. During the consultation process, some stakeholders supported the amendment. One stakeholder opined that MSOs/DPOs should increase the capacity of their systems to activate STBs seamlessly without any glitch. Low transactional capacity of MSOs/DPOs result in loss to the subscribers and broadcaster. Another stakeholder suggested that the subscriber base may not be the appropriate criteria to assess the capacity of CAS and SMS, more so, in the current framework when a single customer can generate more than one transaction in terms of activation/deactivation of channel, recharge, etc. Therefore, they suggested that the criteria of 5% should be measured in context to total volume of transactions.

20. Taking into considerations all the comments received during the consultation process and internal analysis, the authority is of the view that the CAS and the SMS should be able to activate or deactivate services or STBs of at least Five percent (5%) of the subscriber base of the distributor within 24 hours.

Fingerprinting – Support for Visible and Covert fingerprinting in STBs

21. There are issues related to the availability of both visible and covert fingerprinting on all the STBs. Based on industry information, it has been ascertained that not all the deployed STBs provide both types of fingerprinting. Before the Interconnection Regulations 2017, the STBs with overt fingerprinting would suffice to comply with the regulations. Therefore, some of the distributors have represented that the set-top boxes deployed prior to the year 2017 does not support covert fingerprinting as they were not mandated by The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) Regulations, 2012. The BIS standards also did not mandate both overt and covert fingerprinting.

22. Quite-a-few number of distributors have requested the authority to review the Schedule III of Interconnection Regulations 2017 in view of the above-mentioned inconsistency. These stakeholders are of the opinion that the system requirement of covert fingerprinting specified in Interconnection Regulations 2017 should be applicable only on the set-top boxes which are deployed after the coming into effect of the Interconnection Regulations, 2017 and not on the boxes deployed before that. Some stakeholders have opined that given that average life of an STB is around 3 years, all such old STBs will get retired within next two years.

23. Noting the inconsistency, the Draft Regulations mentioned that the STB deployed after coming into effect of Interconnection Regulations 2017 should only be mandated to support the covert finger printing.

24. During the consultation process, some stakeholders suggested that there should be a sunset date. Some stakeholders suggested that all the STBs deployed shall support covert fingerprinting for all pay channels by sunset date of 1 July, 2020. According to one stakeholder, covert fingerprint is a vital tool to detect piracy on the ground and it should be made applicable all across India. TRAI should come up with a deadline for DPOs to replace their existing technologies/ STBs with covert fingerprinting technology.

25. Keeping in view all the comments and suggestions the Authority is of the view that the STB deployed after coming into effect of these Amendment regulations shall support the covert finger printing. Given the life-span of STB, it is but natural that in due course all STBs in network will become compliant to both covert and overt fingerprinting. Therefore, to include any specific regulation for the same is redundant.

Watermarking of Network Logo by the DPO

26. The 'watermarking' logo can be inserted at the encoder end before combining of all the signals by a DPO. Alternatively, a DPO can introduce the 'Watermarking' through their middleware provided in the STB.

27. Para 13 of part B of Schedule III of Interconnection Regulations 2017, states that, 'The watermarking network logo for all pay channels shall be inserted at encoder end only'.

28. Many DPOs have requested TRAI that the 'Watermarking' network logo can be inserted by the encoder itself, only when the encoders have this feature. However, many of encoders deployed currently by such MSOs are part of their legacy system and do not have the provision for water marking logo insertion.

29. Considering the issue and the cost implications on legacy systems, the Draft Regulations mentioned that the encoders deployed after coming into effect of Interconnection Regulations 2017 should only be mandated to support watermarking network logo for all pay channels at the encoder end.

30. During the consultation process, some stakeholders suggested that there should be a sunset date. Some stakeholders suggested that all the encoders deployed shall support watermarking network logo for all pay channels at the encoder end by sunset date of 1 July, 2020. According to one stakeholder, there has been a rise of online piracy in the industry. In the case of absence of the watermarking logo, there is possibility of manifold increase in instances of piracy. There should be a provision to retain watermarking clause and encoders currently present in the market should be directed to be replaced by encoders, which have the feature to support watermarking logo for pay channels, to get a curb on piracy.

31. Taking into considerations all the comments, the Authority is of the view that the encoders deployed after coming into effect of these Amendment regulations shall support watermarking network logo for all pay channels at the encoder end.

Digital Rights Management (DRM)

32. DRM is a systematic approach to copyright protection for digital media. The purpose of DRM is to prevent unauthorized redistribution of digital media and restrict the ways consumers can copy content they've purchased. DRM products were developed in response to the rapid increase in online piracy of commercially marketed material, which proliferated through the widespread use of peer-to-peer file exchange programs. Typically, DRM is implemented by embedding code that prevents copying, specifies a time period in which the content can be accessed or limits the number of devices the media can be installed on. DRM technology focuses on making it impossible to steal content in the first place, a more efficient approach to the problem than the hit-and-miss strategies aimed at apprehending online poachers after the fact.

33. The Schedule III of the Interconnection Regulations 2017 does not provide for the requirements / specifications of DRM based systems. The Authority, during its consultations on Audit manual, received the feedback that owing to its benefits the IPTV based DPOs are switching to DRM technology. It is necessary that the Audit regime covers the DRM based networks and provides for enabling provisions for such operators. Accordingly, Draft Regulations included DRM specifications in Schedule III.

34. During the consultation process, the Authority received numerous comments and suggestions from various stakeholders on this issue. Numerous modification/additions were proposed by several stakeholders. Hence, the Authority is of the opinion that system requirements for DRM shall be dealt with in a separate consultation paper.

Other issues

35. In addition to the amendments proposed in the Schedule III of the Interconnection Regulations, 2017 on issues related to scope and scheduling of audits, transactional capacity of CAS and SMS system, covert fingerprinting, watermarking logo and DRM, the Authority received a large number of comments from several stakeholders on other clauses of Schedule III. Several stakeholders suggested modifications on other clauses of Schedule III. Suggestions were also received on additional clauses/ sections to be included in Schedule III.

36. The Authority is of the opinion that most of these suggestions were related with Audit process and has been discussed at length during the consultation process of the Audit Manual. Further, issues related to DRM need to be discussed during separate consultation process. Other issues have been discussed pointwise in this Explanatory Memorandum.

37. In addition, a representation dated 20.09.2019 was received from M/s. Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL), wherein they informed TRAI that the name of BECIL has not been mentioned in carrying out the audit under Section 15 of the Interconnection Regulations 2017 whereas regulation 10 of Interconnection Regulations 2017 mandates BECIL or any other empaneled agencies of TRAI to conduct the audit. BECIL mentioned that in view of this many MSOs who wish to take the services of BECIL in carrying out the audit under regulation 15 are not able to do so. BECIL has been conducting technical as well as commercial audits under earlier interconnection regulations of TRAI of 2004, 2009 and 2012 regularly as well as Hon'ble TDSAT directed audits which include both commercial as well as technical audits. BECIL further mentioned that it appears that in regulation 15, mention of BECIL's name has been left inadvertently. Therefore, BECIL requested that they should also be nominated for conducting the commercial audit under regulation 15, in addition to the empaneled auditors of TRAI, keeping in view BECIL's vast experience and expertise in conducting these audits since last 10 years. BECIL also raised this issue in the OHD conducted on the Draft Regulations. During the OHD, the Authority consulted all the stakeholders on this issue, and it was felt that BECIL's name may be included in regulation 15.

38. Accordingly, the Interconnection Regulations 2017 dated the 3rd March, 2017, have been amended.